भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.07.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1688 का उत्तर

मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी

1688. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में रेल संपर्क का विस्तार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन के संबंध में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंदौर-मनमाड रेल परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

s.k

मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के संबंध में 27.07.2022 को लोक सभा में श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल के अतारांकित प्रश्न सं. 1688 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ख): परियोजनाएं क्षेत्रीय-वार स्वीकृत की जाती है न की राज्य-वार/जिला-वार, क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 84,470 करोड़ रुपये की लागत की 5,872 कि.मी. लंबाई वाली 33 परियोजनाएं (08 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) जिसमें इंदौर रेलवे स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु इंदौर को अन्य स्थानों से जोड़ने वाली परियोजनाएं भी शामिल है, योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। जिसमें से 1,319 कि.मी. लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2022 तक 23,779 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- **36,163 करोड़ रुपये की लागत की 1,979 कि.मी. लंबाई वाली 08 नई लाइन परियोजनाएं, जिसमें से 355 कि.मी. को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2022 तक 6,606 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**
- **10,764 करोड़ रुपये की लागत की 780 कि.मी. लंबाई वाली 02 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिसमें से 279 कि.मी. को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2022 तक 3,015 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**
- **37,542 करोड़ रुपये की लागत की 3,113 कि.मी. लंबाई वाली 23 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिसमें से 685 कि.मी. को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2022 तक 14,159 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।**

मध्य प्रदेश, भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ज़ोनों द्वारा कवर किया गया है। निधि आवंटन और व्यय का परियोजना-वार और क्षेत्रीय-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates

s.k

>Finance (Budget)>Pink book (year) > Railway-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

2014 से, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 2014-19 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आबंटन, 2009-14 के दौरान 632 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,213 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन की तुलना में 567% अधिक है। इन परियोजनाओं के लिए 2019-20 में बजट आवंटन 6,906 करोड़ रुपये (2009-14 के लिए औसत वर्षित बजट आवंटन से 993% अधिक) तक बढ़ा दिया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में 6,509 करोड़ रुपये तक (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 930% अधिक) और 2021-22 में 9,041 करोड़ रुपये तक (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 1331% अधिक) बढ़ा दिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 12,110 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन प्रदान किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन (623 करोड़ रु. प्रतिवर्ष) से 1816% अधिक है।

2014-22 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाले 1515 कि.मी. के खंड (293 कि.मी. नई लाइन, 631 कि.मी. आमान परिवर्तन और 591 कि.मी. दोहरीकरण) को 189.38 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है, जो 2009-14 (29 कि.मी./वर्ष) के दौरान की गई कमीशिनिंग से 5530% अधिक है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, इंदौर को जोड़ने के लिए कोई भी हाई स्पीड रेल कॉरिडॉर विचाराधीन नहीं है।

(ङ): मनमाड- इंदौर (358 किमी) नई लाइन परियोजना को रेल बजट 2016-17 में शामिल किया गया था जो सरकार से अपेक्षित अनुमोदन के अध्याधीन है। जुलाई 2017 में इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी। डीपीआर के अनुसार, परियोजना की लागत 8857.97 करोड़ रु. आंकी गई थी।

इससे पहले, रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय की भागीदारी नीति के संयुक्त उद्यम (जेवी) मॉडल के तहत परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित कर

दिया है। तदनुसार, इस परियोजना को निष्पादन एजेंसी के रूप में भारतीय पोर्ट रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के साथ शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके बाद, जेएनपीटी की अन्य परियोजनाओं में निवेश करने की योजना के मद्देनजर, उल्लिखित परियोजना में निवेश स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच को भी रेल परियोजना के रूप में माना गया है।

******

s.k